हाशिये से मुख्यधारा तक
भारतीय जन जातीय समुदायों के लिए एक नई सुबह

14 जून, 2025

<u>आदिवासी समुदायों के साथ एक नया भारत</u>

भारत में दुनिया की सबसे जीवंत और विविध आदिवासी आबादी में से एक है। 10.45 करोड़ से अधिक आदिवासी नागरिकों के साथ, जो कुल आबादी का 8.6% है, आदिवासी समुदाय भारत के सभ्यतागत ताने-बाने का अभिन्न अंग रहे हैं। उन्होंने समृद्ध परंपराओं, भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित किया है जो देश की सांस्कृतिक पहचान को आकार देते हैं। उनका योगदान कालातीत है, रामायण और महाभारत में उनके ज्ञान, वीरता और प्रकृति के साथ गहरे संबंध को उजागर करने वाले संदर्भ हैं।

अपनी समृद्ध विरासत के बावजूद, आदिवासी समुदायों को ऐतिहासिक रूप से मुख्यधारा के विकास की कहानी से बाहर रखा गया है। दशकों

तक, उन्हें प्रगति में समान भागीदार के बजाय संस्कृति के संरक्षक के रूप में देखा गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, प्रतीकात्मकता से लक्षित सशक्तिकरण की ओर एक स्पष्ट और जानबूझकर बदलाव हुआ है। इसे केंद्रीय बजट 2025-26 ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए धन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जो समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो वास्तव में किसी को पीछे नहीं छोड़ता है।

<u>जनजातीय विकास के लिए मजबूत बजटीय सहायता</u>

पिछले दशक में, भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय का वार्षिक बजट तीन गुना हो गया है, यह 2013-14 में 4,295.94 करोड़ रु से बढ़कर 2025-26 में 14,926 करोड़ रु हो गया है, जो समावेशी विकास के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

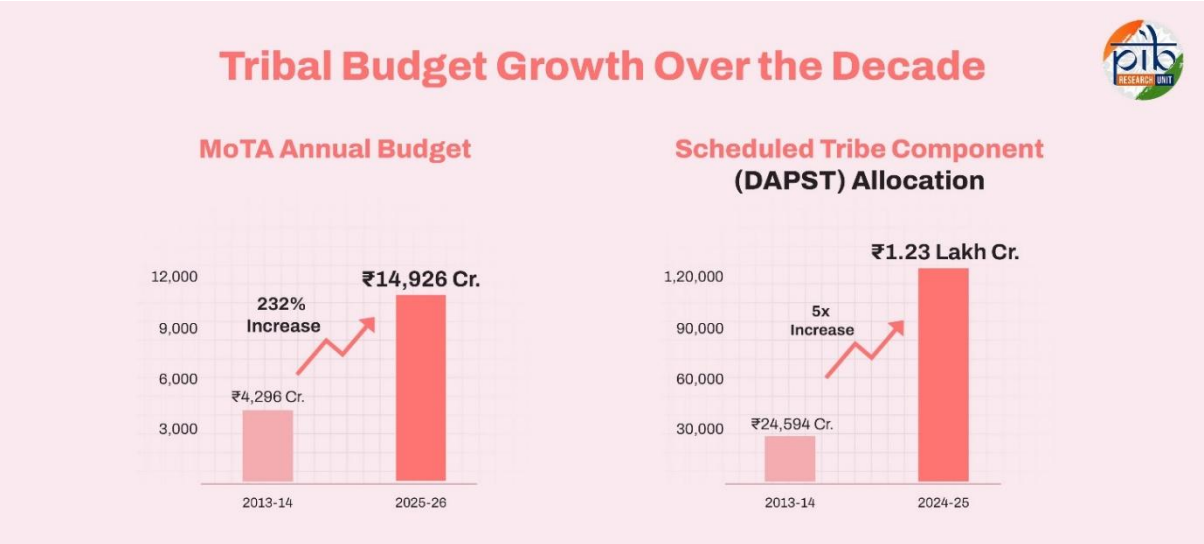

प्रमुख योजनाओं को पर्याप्त धनराशि प्राप्त हुई है, जिसमें पीएम-

जनमन के लिए 24,104 करोड़ रु और धरती आबा अभियान के लिए 79,156 करोड़ रु शामिल हैं, जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों का समग्र विकास करना है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) में 2013-14 के 24,598 करोड़ रु से बढ़कर 2024-25 में 1.23 लाख करोड़ रु की पाँच गुना वृद्धि देखी गई है। जिसमें 42 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अब एसटी-केंद्रित पहलों में योगदान दे रहे हैं। यह क्रॉस-सेक्टरल दृष्टिकोण आदिवासी शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे और आजीविका में व्यापक और निरंतर प्रगति सुनिश्चित करता है।

वन अधिकार अधिनियम: आदिवासी भूमि और आजीविका को सुरक्षित करना

वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) आदिवासी और वन-निवासी समुदायों को वन भूमि और संसाधनों पर उनके व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता देकर सशक्त बनाता है। पिछले दशक में, सरकार ने 17 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में एफआरए सेल, क्षमता निर्माण और जागरूकता अभियान के माध्यम से इसके कार्यान्वयन को मजबूत किया है।

धरती आबा अभियान के तहत, समर्पित फंडिंग आजीविका विकास और दावे के बाद सहायता का समर्थन करती है। दावों की प्रक्रिया को तेज़ करने और ज़मीनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मंथन शिविर और 2025 में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट सम्मेलन सहित राष्ट्रीय स्तर की बैठकें आयोजित की गईं। भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने और टिकाऊ वन-आधारित आजीविका को सक्षम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

वन अधिकार के कार्यान्वयन में प्रगति

मार्च 2025 तक का विवरण

ब्यौरा	मार्च 2025 तक
वितरित की गई कीगईअधिकार पत्रों की संख्या	23.88 लाख
समुदायोंकोदिए गए अधिकार पत्र	1.21 l akh
दावों का निपटान	43.72 लाख
निहितभूमिक्षेत्र (एकड़में)	232.66 लाख एकड़

धरातल से भविष्य का निर्माण

1. पीएम-जनमन: भारत की सबसे कमज़ोर जनजातियों के लिए जीवन रेखा

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) सिर्फ़ एक योजना न होकर - भारत के विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए न्याय, सम्मान और उत्थान का एक शक्तिशाली मिशन है। समग्र विकास के दृष्टिकोण से शुरू की गई यह पहल 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 75 पीवीटीजी समुदायों के जीवन में परिवर्तन ला रही है, और देश के सबसे दूरदराज के इलाकों तक पहुँच रही है।

24,104 करोड़ रुपये के बड़े निवेश के साथ, पीएम-जनमन तीन साल की अवधि में बुनियादी सुविधाओं - आवास, पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पोषण, सड़क और स्थायी आजीविका - तक लोगों की पहुँच सुनिश्चित करके दशकों की उपेक्षा को दूर कर रहा है।

मंत्रालय	गतिविधि	मिशन लक्ष्य (2023–2026)	स्वीकृत विवरण	भौतिक उपलब्धियाँ
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकानों का प्रावधान	4.90 लाख मकान	4,34,837 मकान	1,04,688 मकान पूरे हुए
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू)	733 एमएमयू	687 एमएमयू	687 एमएमयू 38 लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति के साथ क्रियाशील
जल शक्ति मंत्रालय	पाइप जलापूर्ति	19,375 गाँव	18,379 गाँव	7,202 गाँव 100% संतृप्त
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और	2,500 आंगनवाड़ी	2,139 आंगनवाड़ी	1,069 आंगनवाड़ी केंद्रों का

मंत्रालय	गतिविधि	मिशन लक्ष्य (2023–2026)	स्वीकृत विवरण	भौतिक उपलब्धियाँ
	संचालन			संचालन शुरू
शिक्षा मंत्रालय	छात्रावासों का निर्माण और संचालन	500 हॉस्टल	243 हॉस्टल	95 छात्रावासमें काम शुरू
संचार मंत्रालय	मोबाइल टावरों की स्थापना	4,543 बस्तियों का कवरेज	3,679 बस्तियाँ	2,271 बस्तियाँ कवर की गईं
बिजली मंत्रालय	अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण	1,42,133 परिवार	1,42,133 परिवार	1,05,760 घरों का विद्युतीकरण
नवीन और नवीकरणीय	घरों के लिए सौर ऊर्जा	पात्र लाभार्थियों	9,961 घरों को मंजूरी	2,057 घरों का

मंत्रालय	गतिविधि	मिशन लक्ष्य (2023–2026)	स्वीकृत विवरण	भौतिक उपलब्धियाँ
ऊर्जा मंत्रालय		की पहचान		विद्युतीकरण
जनजातीय मामलों का मंत्रालय	बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) की स्थापना	1,000 एमपीसी	1,000 एमपीसी	612 एमपीसी में निर्माण कार्य प्रगति पर; 38 एमपीसी पूरे हो गए

2. <u>धरती आबा अभियान: गांव-गांव आदिवासी को बदलना</u>

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी और समग्र विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक ऐतिहासिक पहल है जो सुनिश्चित करती है कि शासन का लाभ हर आदिवासी नागरिक तक पहुंचे। यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के प्रति भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है और आदिवासी समुदायों को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में रखता है।

2 अक्टूबर, 2024 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया

गया यह अभियान पीएम-जनमन की सफलता पर आधारित है और आदिवासी गांवों को अवसर और सम्मान के केंद्रों में बदलने की दिशा में एक शक्तिशाली कदम का प्रतिनिधित्व करता है। 79,156 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण निवेश के साथ, यह बहु-क्षेत्रीय पहल 25 एकीकृत हस्तक्षेपों के माध्यम से 17 मंत्रालयों को एक साथ लाती है, जो जमीनी स्तर पर विकास के लिए एक व्यापक मॉडल पेश करती है।

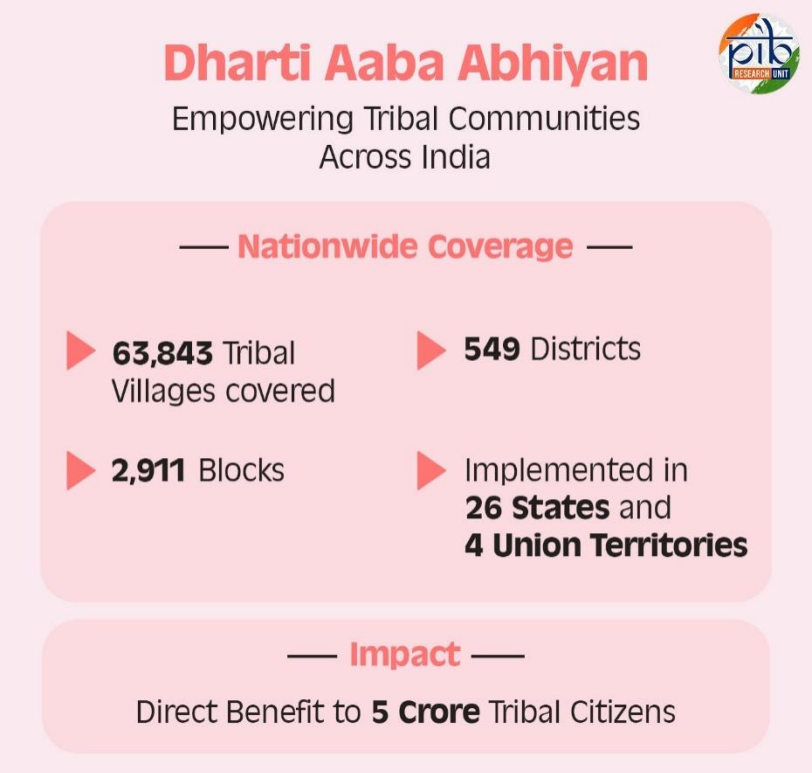

<u>अंत्योदय द्वारा निर्देशित: अंतिम व्यक्ति तक सबसे पहले</u>

यह अभियान अंत्योदय के सिद्धांत को मूर्त रूप देता है, यह सुनिश्चित करता है कि विकास सबसे वंचित और दूरदराज के आदिवासी समुदायों तक पहुंचे। यह बुनियादी ढांचे और बुनियादी सेवाओं में महत्वपूर्ण अंतराल को संबोधित करता है, इस पर ध्यान केंद्रित करके:

स्वच्छ पेयजल तक पहुंच के साथ सुरक्षित और स्थायी आवास

बेहतर स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता सुविधाएं

बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पोषण सहायता

विश्वसनीय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना

आदिवासी क्षेत्रों में सड़क संपर्क और डिजिटल नेटवर्क का विस्तार

योजनाओं और कौशल के अभिसरण के माध्यम से सतत आजीविका के अवसर

<u>धरती आबा अभियान की प्रगति की मुख्य विशेषताएं</u>

	हस्तक्षेपकाक्षेत्र	लक्ष्यएवंउपलब्धियां
लाभार्थीह स्तक्षेप	**आवास**	11.45 लाखमकानस्वीकृतकियेगयेऔर7 6,704 मकानपूरेकियेगये.
	विद्युतीकरण	1,84,551 घरेलूविद्युतीकरणकनेक्शनस्वीकृतकिएगएतथा3,827 सार्वजनिकस्थानोंकोमंजूरीदीगई.
	पेयजलआपूर्ति	62,515 गांवोंकोमंजूरीदीगईतथा 25,870 गांवोंकोसंतृप्तकियागया।
	एफआरएपट्टाधारकोंकोकृषिसहायता	चारराज्योंअसम, मध्यप्रदेश, ओडिशाऔरजम्मू-कश्मीरकेलिएप्रस्तावोंकोमंजूरीदीगईजिससे 1,73,097 लाभार्थीलाभान्वितहोंगे।

	हस्तक्षेपकाक्षेत्र	लक्ष्यएवंउपलब्धियां
	जनजातीयमछुआरोंकोमछलीपालनमेंसहायता	10 राज्यों/केंद्रशासितप्रदेशों: असम, झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचलप्रदेश,मध्यप्रदेशकेलिए आदिवासीमछुआरोंको52.18 करोड़रु कीसहायताकेप्रस्तावोंकोमंजूरीदी गईहै।,.
सामुदायिकहस्तक्षेप	आश्रमविद्यालयों / जनजातीयआवासीयविद्यालयोंकाउन्नयन	.3,420 परियोजनाएंस्वीकृत
	जनजातीयबहुउद्देशीयविपणनकेंद्र (टीएमएमसी)	5 लाखसेअधिकलाभार्थियोंकोकवर करनेवाली 71 टीएमएमसीकोमंजूरीदीगई।
	सिकलसेलरोगकेलिएसक्षमताकेंद्र (सीओसी)	14 राज्योंमें15 सीओसीकोमंजूरीदीगई.
	सामुदायिकवनसंसाधनअधिकारप्रबंधनयोजनाएँ (सीएफआरएमयोजनाएँ)	90,000 हेक्टेयरसेअधिकवनभूमिकोकवर करनेवाली 920 सीएफआरएमयोजनाएंस्वीकृतकी गईं।

	हस्तक्षेपकाक्षेत्र	लक्ष्यएवंउपलब्धियां
	धरतीआबाएफआरएसेल	17 राज्यों/केंद्रशासितप्रदेशोंकेलिए17 राज्यस्तरीयएफआरएप्रकोष्ठोंऔर 19 राज्यों/केंद्रशासितप्रदेशोंमें414 जिलास्तरीयप्रकोष्ठोंकोमंजूरीदीगई।
	मोबाइलमेडिकलयूनिट (एमएमयू)	36 एमएमयूकासंचालनशुरू।
	हॉस्टल	604हॉस्टल स्वीकृत।
	आंगनवाड़ीकेंद्र	236आंगनवाड़ीकेंद्रस्वीकृत।
	दूरसंचारकनेक्टिविटी	4,543 गांवोंकोमंजूरीदीगईऔर2,983 गांवोंकोकवरकियागया.

<u>जनजातीय गौरव दिवस: जनजातीय विरासत का सम्मान</u>

भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समुदायों के अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए, भारत सरकार हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाती है। 2024 का उत्सव उनकी 150वीं जयंती के रूप में मनाया जाएगा, और इस अवसर पर देश भर में गर्व, भागीदारी और जनजातीय विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से नीति-संचालित कार्यान्वयन किए जाएंगे।

2024 के जनजातीय गौरव दिवस में 1 करोड़ से अधिक लोगों की वर्चुअल भागीदारी देखी गई। बिहार के जमुई में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में माननीय प्रधान मंत्री ने भाग लिया, जिसमें जनजातीय योगदान के महत्व को रेखांकित किया गया। जनजातीय नायकों को सम्मानित करने के लिए, 10 राज्यों में 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्वीकृत किए गए। 15-26 नवंबर 2024 के बीच, देश भर में 46,000 से अधिक गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कला और संस्कृति आदि जैसे विषय शामिल थे। आदि महोत्सव और धरती-आबा ट्राइबप्रेन्योर्स जैसे कार्यक्रमों में आदिवासी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जबकि 29 आदिवासी शोध संस्थान, (टीआरआई) उत्सव, सेमिनार और छात्र-नेतृत्व वाले कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे। बिहार, नागालैंड, गोवा, केरल, असम और मिजोरम में भी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

<u>आगे रहने के लिए सीखना: सशक्त बनाने वाली शिक्षा</u>

पिछले एक दशक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) पहल, जो पूरे भारत में आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है,में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। नीति, बुनियादी ढाँचे, शिक्षाविदों और डिजिटल नवाचार में सरकार के रणनीतिक हस्तक्षेपों ने आदिवासी युवाओं के लिए पहुँच, शासन और सीखने के परिणामों में काफ़ी सुधार किया है। ईएमआरएसस्कूल अब हर आदिवासी ब्लॉक में स्थापित किए गए हैं, जहाँ 50% से ज़्यादा

ST आबादी है और कम से कम 20,000 आदिवासी निवासी हैं (2011 की जनगणना के अनुसार)। मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख ST छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728ईएमआरएसस्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

ईएमआरएसका परिवर्तनकारी विकास (2004-2024)

ब्यौरा	2004–2014	2014–2025
कुलस्वीकृतस्कूल	90	555
चल रहे स्कूल	82	354
भवन निर्माण पूरा	63	279
प्रतिछात्रआवर्तीलागत	42,000रु	1,47,000रु
प्रतिविद्यालयनिर्माणलागत (साधा .)	12 करोंड़ रु	38 करोंड़ रु
प्रतिविद्यालयनिर्माणलागत (पहाड़ी/पूर्वोत्तर/वामपंथीउग्रवाद)	16 करोंड़ रु	48 करोंड़ रु
कुलबजटआवंटन	सीमित	28,920 करोड़ (2021–26)
शिक्षकएवंगैर-शिक्षणकर्मचारियोंकीभर्ती	अनौपचारिक	9,000+
कर्मचारियोंकीनईभर्ती (2019–2026)	अनुपलब्ध	38,480 अनुमत

छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाना

पिछले 11 वर्षों में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने विस्तारित कवरेज, बढ़ी हुई फंडिंग और डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाने के लिए अपने छात्रवृत्ति पारिस्थितिकी तंत्र को काफी मजबूत किया है। आज, पाँच केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं से सालाना लगभग 30 लाख आदिवासी छात्र लाभान्वित होते हैं, जिनका बजट परिव्यय 2013-14 में 978 करोड़ रु से बढ़कर 2024-25 में 3,000 करोड़ रु से अधिक हो गया है।

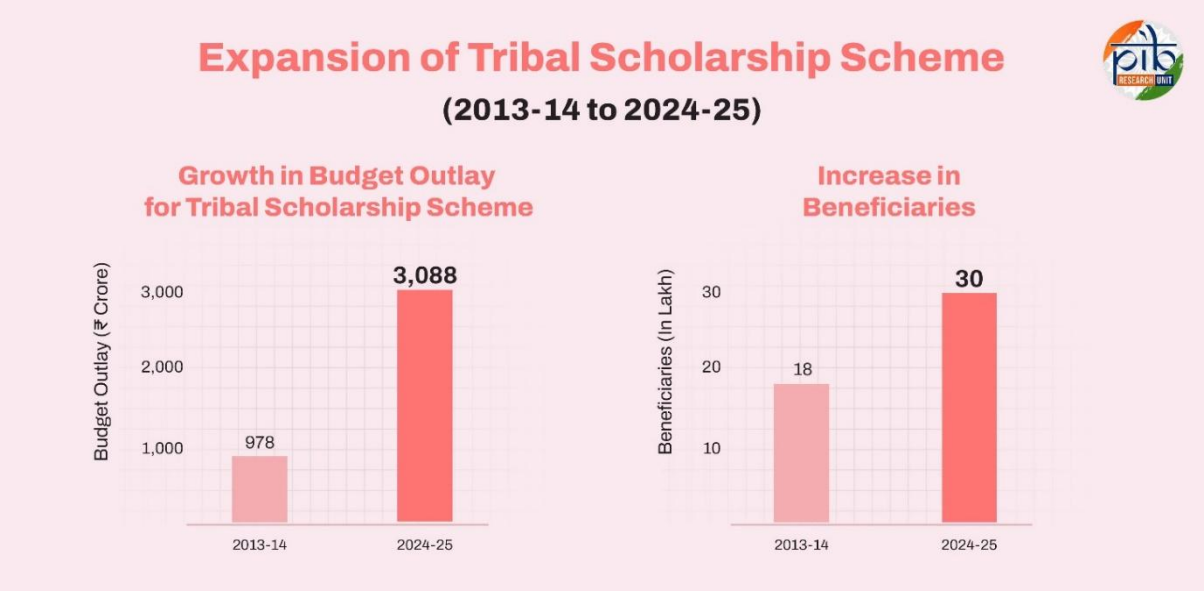

मैनुअल से पूरी तरह से डिजिटल, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)-सक्षम प्रणालियों में बदलाव एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा है, जिससे पिछले दशक में 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति का तेज़, पारदर्शी और वास्तविक समय पर वितरण हुआ है। विभिन्न योजनाओं के तहत समर्थित छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है - एमफिल/पीएचडी फेलोशिप ~950 से बढ़कर 2,700 हो गई,

राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति 8 से बढ़कर 58 छात्र हो गई, और शीर्ष श्रेणी की शिक्षा योजना कवरेज दोगुनी से अधिक हो गई, जिससे आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे प्रमुख संस्थानों में 7,000 छात्र लाभान्वित हुए।

<u>जनजातीय आबादी के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की पहल</u>

<u>सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन</u>

आदिवासी आबादी के बीच स्वास्थ्य असमानताओं को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत, भारत सरकार ने 2023 में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया। केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित और 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किए गए इस मिशन का उद्देश्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया (एससीए) को खत्म करना है, जिसमें आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इसका लक्ष्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 0-40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ व्यक्तियों की जांच करना है।

2025 तक 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है।

19 जून से 3 जुलाई 2024 तक देश भर में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें शामिल थे:

- 1.60 लाखकार्यक्रम
- 1 लाख स्वास्थ्य शिविर
- 13.19 लाख स्क्रीनिंग कार्ड का वितरण

एससीए जागरूकता और परामर्श के लिए क्षमता निर्माण हेतु जनवरी 2025 में दिल्ली में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

उन्नत निदान, उपचार और रोगी सहायता प्रदान करने के लिए धरती आबा अभियान के तहत 14 राज्यों में 15 सक्षमता केंद्र (सीओसी) स्थापित किए गए।

एम्स दिल्ली ने आदिवासी स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें हेमाटोलॉजी पर फोकस रहते हुए आदिवासी स्वास्थ्य के भगवान बिरसा मुंडा चेयर की स्थापना, ओडिशा में स्वास्थ्य सेवा विकास के लिए लमटापुट ब्लॉक को अपनाना, साथ ही जनजातीय गौरव वर्ष के दौरान ओडिशा के सुंदरगढ़ में आयोजित मेगा मेडिकल कैंप जैसे शिविरों के लिए समर्थन शामिल है।

यह समन्वित, बहु-एजेंसी प्रयास सरकार के इस संकल्प को रेखांकित करता है कि आदिवासी समुदायों को समय पर निदान, उपचार और देखभाल मिले, जिससे स्वास्थ्य आदिवासी सशक्तिकरण और समावेशन का एक प्रमुख स्तंभ बन जाए।

<u>आदिवासी आजीविका और उद्यमिता</u>

<u>वन धन पारिस्थितिकी तंत्र:</u>

14 अप्रैल 2018 को शुरू की गई वन धन योजना 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपीके लिए मूल्य श्रृंखला के विकास' के तहत एक प्रमुख पहल है। नोडल एजेंसी के रूप में ट्राईफेड द्वारा कार्यान्वित की गई इस योजना का उद्देश्य आदिवासी संग्रहकर्ताओं को उद्यमी बनाकर उनके लिए आजीविका के अवसर पैदा करना है। जनजातीय बहुल जिलों में वन धन विकास केंद्र (वीडीवीकेसी) स्थापित किए गए हैं, जहां जनजातीय स्वयं सहायता समूह

(एसएचजी) लघु वनोपजों के संग्रहण, मूल्य संवर्धन और विपणन में संलग्न हैं।

जनजातीय आजीविका और उद्यम में प्रमुख बदलाव भरी उपलब्धियाँ

आदिवासी उद्यमियों को सशक्त बनाना

- पूरे भारत में 4,030 वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित किए गए
- वन उपज के मूल्य संवर्धन के माध्यम से स्थायी आजीविका उत्पन्न करके 12 लाख से अधिक आदिवासी व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया

लघु वन उपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का विस्तार

- अधिसूचित एमएसपी सूची में 77 नए एमएफपी जोड़े गए
- आदिवासी संग्रहकर्ताओं के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति और आय सुरक्षा सुनिश्चित की गई

<u>बुनियादी ढांचे और बाजार संबंधों को मजबूत करना</u>

- 1,316 हाट बाजार, 603 भंडारण इकाइयाँ और 22 प्रसंस्करण इकाइयाँ स्वीकृत की गईं
- आदिवासी उत्पादों और कारीगरों के लिए सीधे बाजार तक पहुँच की सुविधा प्रदान की गई
- आदिवासी बुनियादी ढाँचे के विकास का समर्थन करने के लिए 89.14 करोड़ रु जारी किए गए

<u>आदिवासी संस्कृति और वाणिज्य को बढ़ावा देना</u>

- देश भर के प्रमुख शहरों में 38 आदि महोत्सव आयोजित किए गए

देश

आदिवासी हस्तशिल्प, कला और कृषि-उत्पादों को व्यापक राष्ट्रीय दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया गया

<u>उच्च-स्तरीय मान्यता और समर्थन</u>

प्रधानमंत्री ने दो बार आदि महोत्सव का उद्घाटन किया, जिससे राष्ट्रीय दृश्यता और समर्थन बढ़ा

भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में झारखंड में 15,000 से अधिक महिला एसएचजी सदस्यों को संबोधित किया, जिससे आदिवासी महिला नेताओं को सशक्त बनाया गया

<u>वित्तीय सशक्तिकरण:</u>

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ने पिछले एक दशक में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनएसटीएफडीसीने रियायती वित्तीय सहायता के माध्यम से आदिवासी उद्यमियों, छात्रों और स्वयं सहायता समूहों को अपना समर्थन काफी हद तक बढ़ाया है।

2014 और 2025 के बीच, निगम ने अपने ऋण स्वीकृतियों और संवितरणों को दोगुना से भी अधिक कर दिया है, अपने लाभार्थियों तक 95% से अधिक की पहुँच का विस्तार किया है, और 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक कवरेज बढ़ाया है। इसके ऋण पोर्टफोलियो में 171% की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व और अधिशेष तीन गुना हो गया, जो मजबूत संस्थागत विकास और प्रभाव का संकेत देता है।

<u>नीति सुधार और रणनीतिक पहल</u> (2014-2025)

1. बढ़ी हुई ऋण सीमाएँ

आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई): ऋण सीमा 50,000 रु से बढ़ाकर 2 लाख रु की गई।

टर्म लोन स्कीम: परियोजना लागत सीमा 10 लाख रु से बढ़ाकर 50 लाख रु प्रति इकाई की गई।

आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (शिक्षा ऋण): सीमा 5 लाख रु से बढ़ाकर 10 लाख रु की गई।

2. आज़ादी का अमृत महोत्सव (2021) के तहत कोहिमा और विशाखापत्तनम में 139 आदिवासी उद्यमियों को सम्मानित किया गया।

3. 650 से अधिक एसटी महिला एसएचजी सदस्यों को वित्तीय साक्षरता, डिजिटल वित्त और सरकारी योजना नेविगेशन में प्रशिक्षित किया गया।

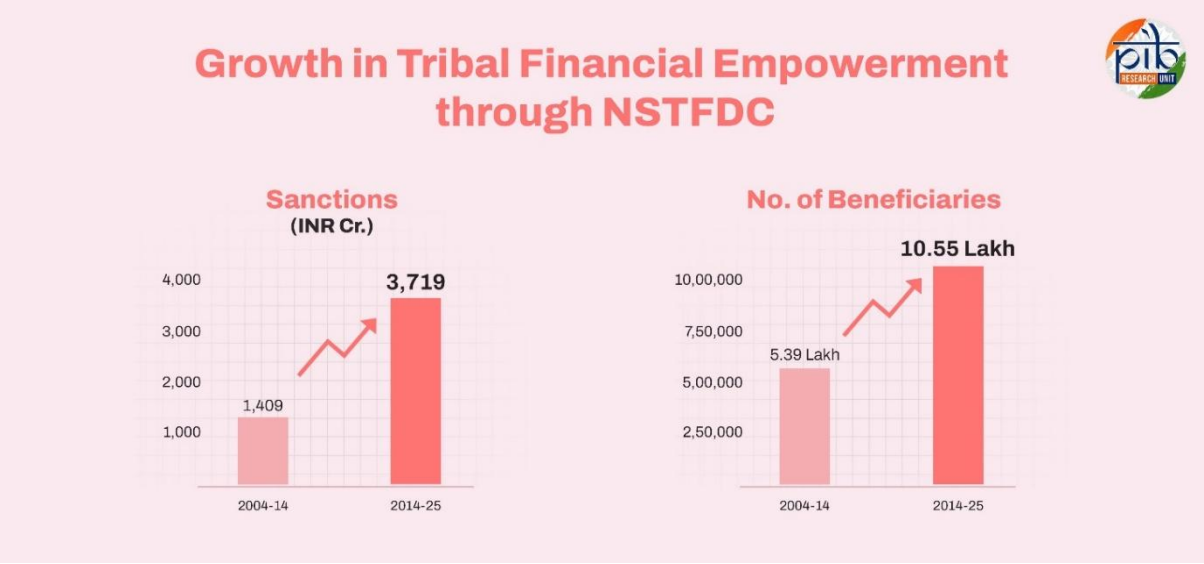

स्टार्टअप और नवाचार:

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) का उद्देश्य उद्यम विकास को बढ़ावा देकर आदिवासी आजीविका को बढ़ावा देना है। यह लघु वनोपज (एमएफपी) के मूल्य संवर्धन के लिए वन धन विकास केंद्र और उत्पादक उद्यम स्थापित करने, एमएसपी खरीद को मजबूत करने और बाजार पहुंच में सुधार के लिए हाट बाजार और गोदाम विकसित करने पर केंद्रित है। ट्राइफेड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो प्रभावी कार्यान्वयन और बाजार संपर्क सुनिश्चित करता है।

पीएमजेवीएम की प्रमुख परिवर्तनकारी उपलब्धियाँ

उपलब्धि के क्षेत्र	Det ai l s
जनजातीयउद्यमियोंका सशक्तिकरण	4,030 वनधनविकासकेंद्र (वीडीवीके) स्थापितकिएगए 12 लाखसेअधिकआदिवासी लाभान्वित हुए
लघुएवंमध्यमउद्यमों (एमएफपी) केलिएएमएसपीकाविस्तार	बेहतरमूल्यप्राप्तिकेलिए 77 नएलघुवनोपज (एमएफपी) वस्तुओं को एमएसपीसूचीमेंजोड़ेगए
बुनियादीढांचाऔरबाजारसंबंध	316 हाटबाज़ारों 603 भंडारणइकाइयाँ 22 प्रसंस्करणइकाइयों

उपलब्धि के क्षेत्र	Det ai l s
	कोमंज़ूरीदीगई बुनियादीढांचेकेविकासकेलिए 89.14 करोड़रुपयेजारीकिएगए
जनजातीयसंस्कृतिऔरवाणिज्यको बढ़ावादेना	प्रमुखशहरोंमें 38 आदिमहोत्सवआयोजितकिएगए प्रधानमंत्रीनेदोबारआदिमहोत्सवकाउद्घा टनकिया राष्ट्रपतिनेझारखंडमें 15,000 सेअधिकमहिलाएसएचजीसदस्योंकोसं बोधितकिया (2023)

<u>अनुसूचित जनजातियों की सूची का विस्तार</u>

आदिवासी समुदायों को मान्यता देने में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, 2014 और 2024 के बीच 117 समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ा गया है, जबकि पिछले दशक में यह संख्या केवल 12 थी। यह 10 गुना वृद्धि पहले से हाशिए पर पड़े समूहों को मान्यता देने और उन्हें विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है

अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने से इन समुदायों के लिए शैक्षणिक और नौकरी आरक्षण से लेकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कानूनी सुरक्षा तक कई तरह के कल्याणकारी लाभों के द्वार खुलते हैं, जिससे राष्ट्र की विकास यात्रा में उनकी पूरी भागीदारी हो पाती है।

निष्कर्ष: जनजातीय भारत का उदय

भारत के आदिवासी समुदाय हाशिये से लौटकर मुख्यधारा में आ गए हैं और राष्ट्र की विकास यात्रा के केंद्र बन गए हैं। पीएम-जनमन, धरती आबा अभियान और वन धन योजना जैसी केंद्रित योजनाओं के माध्यम से सरकार ने सुनिश्चित किया है कि आदिवासी नागरिकों को

अधिकार, अवसर और सम्मान मिले। यह परिवर्तन कल्याण से कहीं आगे बढ़कर न्याय, सशक्तिकरण और समावेशन पर आधारित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और संस्कृति में निवेश के साथ आदिवासी समुदाय अपना भविष्य खुद बना रहे हैं। यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का सार है - एक सच्चा जनजातीय भारत बन रहा है।

संदर्भ

जनजातीय कार्य मंत्रालय

- https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153859&ModuleId=3#:~:text=The%20initiative%2C%20100%25%20funded%20by,of%20tribal%20communities%20across%20India.
- https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/oct/doc202410340680 1.pdf
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2090883
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU5506_6okAa3.pdf?source=pqals
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU560_ILFOB6.pdf?source=pqals

विश्लेषक 13/ सरकार के 11 वर्षों पर सीरीज